



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 885]
No. 885]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 24, 2005/भाद्र 2, 1927
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 24, 2005/BHADRA 2, 1927

जनजातीय कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अगस्त, 2005

का.आ. 1175(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (5) के उपखंड (च) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अन्य कृत्यों को विनिर्दिष्ट करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति (अन्य कृत्यों का विनिर्देश) नियम, 2005 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. आयोग, अनुसूचित जनजातियों के संरक्षण, कल्याण, विकास और उन्नति के संबंध में निम्नलिखित अन्य कृत्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:—
(i) उपाय, जिनको वन क्षेत्र में रहने वाली अनुसूचित जनजातियों को लघु वन उपज के संबंध में स्वामित्व के अधिकार प्रदान करने के लिए किए जाने की आवश्यकता है;
(ii) उपाय, जिनको विधि के अनुसार खनिज स्रोतों, जल-स्रोतों के ऊपर जनजाति समुदायों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए किया जाना है;
(iii) उपाय, जिनको जनजातियों के विकास के लिए और अधिक विकासक्षम जीविका संबंधी युक्तियों के कार्यान्वयन के लिए किया जाना है;
(iv) उपाय, जिनको विकास परियोजनाओं द्वारा विस्थापित जनजाति समूहों के लिए अनुतोष और पुनर्वास की प्रभावकारिता में सुधार के लिए किया जाना है;
(v) उपाय, जिनको जनजाति के अन्य संक्रामण का निवारण करने के लिए और ऐसे व्यक्तियों के, जिनके मामले में अन्य संक्रामण पहले ही हो चुका है, प्रभावी रूप से पुनर्वास के लिए किया जाना है;
(vi) उपाय, जिनको वनों का संरक्षण करने और सामाजिक वनरोपण का दायित्व लेने के लिए जनजाति समुदायों का अधिकतम सहयोग प्राप्त करने तथा उन्हें शामिल करने के लिए किया जाना है;
(vii) उपाय, जिनको पंचायत उपबंध (अनुसूचित क्षेत्र पर विस्तार) अधिनियम, 1996 (1996 का 40) का पूर्ण कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए किया जाना है;
(viii) उपाय, जिनको जनजातियों द्वारा खेती की स्थानांतरित करने की पद्धति को, जिसके परिणामस्वरूप उनका लगातार निःशक्तीकरण होता है और भूमि तथा पर्यावरण में अवनति होती है, कम करने और अंततोगत्वा समाप्त करने के लिए किया जाना है।

[फा. सं. 17014/3/2004—सी एंड एल एम—II]

एस. चटर्जी, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TRIBAL AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd August, 2005

S.O. 1175(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (f) of clause 5 of Article 338A of the Constitution, the President hereby makes the following rules to specify the other functions of the National Commission for the Scheduled Tribes, namely:—

1. **Short title and commencement :—**(1) These rules may be called the National Commission for the Scheduled Tribe (Specification of other functions) Rules, 2005.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. The Commission shall discharge the following other functions in relation to the protection, welfare and development and advancement of the Scheduled Tribes, namely:—
 - (i) Measures that need to be taken over conferring ownership rights in respect of minor forest produce to the Scheduled Tribes living in forest areas;
 - (ii) Measures to be taken to safeguard rights of the tribal communities over mineral resources, water resources etc. as per law;
 - (iii) Measures to be taken for the development of tribals and to work for more viable livelihood strategies;
 - (iv) Measures to be taken to improve the efficacy of relief and rehabilitation measures for tribal groups displaced by development projects;
 - (v) Measures to be taken to prevent alienation of tribal people from land and to effectively rehabilitate such people in whose case alienation has already taken place;
 - (vi) Measures to be taken to elicit maximum cooperation and involvement of tribal communities for protecting forests and undertaking social afforestation;
 - (vii) Measures to be taken to ensure full implementation of the Provisions of Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act, 1996 (40 of 1996);
 - (viii) Measures to be taken to reduce and ultimately eliminate the practice of shifting cultivation by tribals that lead to their continuous disempowerment and degradation of land and the environment.

[F. No. 17014/3/2004-C & LM-II]

S. CHATTERJEE, Jt. Secy.